www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष - 04 | अंक - 347 | जौनपुर, शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की चेतावनी

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को भी चिंताजनक बनी रही। गोलाघाट जिले में धनसिरी (दक्षिण) नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने सार्वजनिक सलाह जारी कर आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने और स्थिति में सुधार होने तक नदी से दूर रहने का का आग्रह किया है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब बाढ़ से 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। एएसडीएमए के नवीनतम बाढ़ बुलेटिन के अनुसार, 39 राजस्व सर्किलों के 481 गांवों में 1,68,701 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 14,382 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है, जिससे कई जिलों में कृषि गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। गोलाघाट बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 54,085 लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बाद शिवसागर (49,515), जोरहाट (27,842) और चराइदेव (21,486) का स्थान आता है। शिवसागर, जोरहाट, लखीमपुर और चराइदेव से भी फसलों को भारी नुकसान होने की खबरें मिली हैं। एएसडीएमए ने कहा कि नुमालीगढ़ में धंसिरी (दक्षिण) नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, हालांकि राज्य में किसी भी नदी में बाढ़ का उच्चतम स्तर दर्ज नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में 133 राहत शिविरों और राहत वितरण केंद्रों को चालू रखा है। कुल 10,111 विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 35,596 अन्य लोगों को राहत वितरण केंद्रों के माध्यम से सहायता मिल रही है। राहत एजेंसियों ने प्रभावित परिवारों में चावल, दालें, खाद्य तेल, पशु चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की हैं। वहीं, बाढ़ से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। गोलाघाट और उदलगुरी जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि फिलहाल किसी के लापता होने की खबर नहीं है। इस आपदा से 41,475 जानवर भी प्रभावित हुए हैं और 365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 40 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।

गोवर्धन परियोजना देश की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम! उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे संपीड़ित बायोगैस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। यह योजना निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी। इससे हमारे किसानों, सहकारी समितियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को लाभ होगा, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। गोवर्धन परियोजना देश की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों, गोबर, प्रेस मड (गन्ने की श्मैलीश), नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य जैव-द्रव्यमान संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करेगी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू की जाएगी और संपीड़ित बायोगैस को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख आधार स्थापित करेगी। सुनिश्चित मांग, लाभकारी और स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से, गोवर्धन देश के बायोगैस जाने के लिए आवश्यक मजबूत और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करेगा।

बृजेश पाठक ने अखिलेश को घेरा, बोले- राजनीति में परिवारवाद ही प्राथमिकता

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें ब्राह्मण वोट के लिए जनेश्वर मिश्रा याद आते हैं और राज करने के लिए सिर्फ अपना परिवार। ब्राह्मण वोट दें, इन्हें गद्दी दिलाएं और ये उस पर अपने परिवार की खड़ाऊँ रखकर राज करेंगे। अच्छा होता कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती का सदुपयोग उनके व्यक्तित्व और उनके समाजवादी विचार से अवगत कराने के लिए किया गया होता। जनेश्वर के बारे बताने से ज्यादा मुझे कोसा गया। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले ब्राह्मणों को याचकों की भांति अपमानित किया गया। यह सब नाटक देखकर जनेश्वर की समाजवादी आत्मा यकीनन दुःखी होगी और सोच रही होगी कि यह सब करने के लिए मेरी ही जयंती मिली थी। बृजेश पाठक ने कहा कि चंद टिकटार्थियों के कारण आज पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करना उचित नहीं। मुझे चाहे जितनी गालियां दीजिए पर ब्राह्मण समाज की गरिमा न गिराइए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी समाजवादी पार्टी (सपा) है जो रामायण मेला के संकल्पक क्रांतिधर्मी चिंतक राममनोहर लोहिया और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के दिखाए समाजवाद के पथ, आदर्श और संस्कारों से पूर्णतया भटक चुकी है। डॉ. लोहिया संसद और विधान सभाओं को सार्थक परिणामों वाली बहस का मंच बनाना चाहते थे, अटलजी उनका पूरा सहयोग करते थे। यायावरी प्रकृति के होने के बावजूद लोहिया संसद सत्र के दौरान पूरा समय बहस व संसदीय संवादों को देते थे। छोटे लोहिया जनेश्वर ने इस परम्परा को बढ़ाया। उन्होंने हमेशा समकालीन आंदोलनों की अगुवाई की लेकिन संसद सत्र के दौरान चर्चाओं को प्राथमिकता देते थे।

12 अगस्त को संसद में चर्चा, पिछली तारीख से नहीं होगा लागू – अमित शाह

मिजोरम, (एजेंसी)। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि विवादित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी और इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब केंद्र सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए कामकाज सुचारू रूप से चलाने को लेकर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है। लालदुहोमा, मिजोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मिले ताकि प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर सकें। इस प्रस्तावित कानून का मकसद विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी को और कड़ा करना है। इसके तहत एक शक्तिशाली अधिकृत संस्था बनाने का प्रावधान है जो उन की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकेगी जिनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। लालदुहोमा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि हमने नए विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि यह विधेयक पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 22 बुनकरों और संस्थाओं को मिलेगा सम्मान, राष्ट्रपति करेंगी पुरस्कार वितरण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र (आरबीसीसी) में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने और देश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में बुनकर समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जाएगा। समारोह का मुख्य आकर्षण 22 पुरस्कारों का वितरण होगा। इनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन पहल, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करेंगे। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार हथकरघा बुनकरों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मानों में शामिल है। यह असाधारण कारीगरी, जीवनभर के समर्पण और भारत की बुनाई परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य संबंधित पक्षों को दिया जाता है, जिन्होंने पारंपरिक कौशल को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाया और रचनात्मकता, गुणवत्ता, नवाचार तथा उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। विजेताओं का चयन विशेषज्ञ समितियों वाली बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा, वस्त्र सचिव नीलम शमी राव और विकास आयुक्त (हथकरघा) वरिष्ठ अधिकारी, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और पुरस्कार विजेता शामिल होंगे।

हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 15वां दिन है और सरकार तथा विपक्ष के बीच गतिरोध अब भी बना हुआ है। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पिछले तीन सप्ताह में कई बार दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के विरोध के कारण बाधित हुई है। हालांकि, हंगामे के बीच सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सफल रही है।मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष दो प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। पहला मुद्दा 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का है। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में संसद के भीतर बयान देने की मांग कर रहा है। दूसरा मुद्दा अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए मिले चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने सरकार से दोनों मामलों पर जवाब देने की मांग की।कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों, खासकर छात्राओं के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया।टैगोर ने अपने नोटिस में लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन और कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि पुलिस कार्रवाई का आदेश किसके स्तर से दिया गया और क्या कार्रवाई कानून तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थी।उन्होंने यह भी पूछा कि घटना में कितने छात्र घायल हुए, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस सांसद ने पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध न्यायिक जांच कराने, छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और सरकार से प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद शुरू करने की मांग की।कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।

हस्तशिल्प विश्वविद्यालय की दिशा में काम जारी, बुनकरों-शिल्पकारों को मिलेगी नई पहचान : आनंदीबेन पटेल

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में हस्तशिल्प विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे बुनकरों, शिल्पकारों और उनके बच्चों को शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने और कारीगरों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। आनंदी बेन ने राजभवन स्थित जनभवन में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान नाबार्ड के सहयोग से बागपत, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, हापुड़ और उन्नाव समेत प्रदेश के 13 जिलों के बुनकरों एवं शिल्पकारों की हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने हस्तनिर्मित वस्त्रों और उत्पादों की गुणवत्ता, कलात्मकता तथा पारंपरिक शिल्पकला की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने बुनकरों और शिल्पकारों से संवाद कर उनके उत्पादों के विपणन, बिक्री और आजीविका से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 'क्राफ्ट्स रूट्स' संस्था निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में 17 हस्तशिल्पियों को डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की जा चुकी है। इससे स्थानीय शिल्प को नई पहचान मिली है ।

कांग्रेस ने गोवा इकाई के लिए नई सोशल मीडिया टीम नियुक्त की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने शुक्रवार को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और समन्वयकों की नियुक्ति की घोषणा की। सरकार एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एआईसीसी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

इसके अनुसार, हिमांशु तिवरेकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लिंकन गोम्स और अजमल सैयद को उपाध्यक्ष बनाया गया है।समन्वयकों की सूची में सोहन शेनाई, मैकलिन फर्नांडीस, प्रतिभा बोरकर, ग्लेन लार्सेडा और अरमांडो फेरेरा अल्वारेस शामिल हैं। ये नियुक्तियां गोवा में पार्टी की संगठनात्मक संरचना और डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया विभाग पार्टी के संदेश को प्रसारित करने, विपक्षी बयानों का खंडन करने और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।गोवा में कांग्रेस नेताओं ने नई टीम का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इन नियुक्तियों से संचार रणनीति में सुधार होगा और राज्य की जनता से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिलेगी। विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह गोवा से संबंधित मुद्दों पर पार्टी के कार्यक्रमों, उपलब्धियों और रुख को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर त्वरित प्रतिक्रिया भी देगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश भर की राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया को लामबंदी और जनभागीदारी के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अधिक महत्व दे रही हैं। नए नेतृत्व के आने से, कांग्रेस की गोवा इकाई से आने वाले महीनों में अपने डिजिटल अभियानों को तेज करने की उम्मीद है।

मवई पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर किया दो आरोपियों को गिरफ्तार

अयोध्या। अयोध्या पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया।थाना मवई पुलिस ने इसमें शामिल दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. हफीजुर रहमान और सोहेल खान (निवासी गोरखपुर) के रूप में हुई।आरोपियों के कब्जे से हरियाणा की 839 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।बरामद शराब में 224 बोतल (750 एम एल) और 615 बोतल (375 एम एल) रायल ग्रीन क्लासिक ब्लैडेंड व्हिस्की शामिल है।पुलिस ने इसमें शामिल एक कार को भी बरामद किया।आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और 2,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए।इस संबंध में को रुदौली अरविंद सोनकर ने बताया शुक्रवार को सुबह करीब 3:35 बजे विशेष अभियान के दौरान यह कार्यवाही की गई।बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाना मवई में मु.अ.सं. 87/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही में जुटी है। बताया कि इस खुलासे मे थानाध्यक्ष मवई मनोज कुमार,प्रभारी चौकी रामदास नगर आयुष यादव, उप निरीक्षक शिवम सिंह, अवधेश यादव सहित अनुसार पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।

संपादकीय

विश्वसनीय संकेत अभी नहीं

नए बिल और निलेकणी समिति के गठन से समस्याएं दूर हो जाएंगी? संभवत नहीं, क्योंकि वजह तकनीकी कमजोरियां नहीं हैं। इसके कुछ कारण नीतिगत हैं, तो कुछ सिस्टम में अंदर तक पहुंचा कथित भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में उभरी खामियों का तकनीकी समाधान पेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा कानूनी उपाय के जरिए अपने सख्त इरादे का संदेश देने का प्रयास उसने किया है। मगर अंदाज वही पुराना हैरू मीडिया में मोटी सुर्खियां बनाने वाली घोषणाएं करना, जिससे लोग मानने लगें कि सरकार सब कुछ दुरुस्त करने के लिए सचमुच दृढ़–संकल्प है! इस साल नीट पेपर लीक होने के बाद ऐसी ही धारणा बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र वायु सेना के विमान से भेजे जाएंगे! उसी राह पर चलते हुए अब केंद्र ने पेपर लीक से संबंधित कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाने का बिल पेश किया है। मगर सख्त कानून, अत्यधिक कड़ी सजा के प्रावधान, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी बातें विभिन्न मामलों में इतनी बेअसर साबित हुई हैं कि उनसे युवा वर्ग को संतुष्ट करना अब कठिन हो सकता है। परीक्षा तंत्र को तकनीकी रूप से दुरुस्त करने के उपाय सुझाने के लिए नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में बनी समिति उपजी शिकायतों को दूर कर पाएगी, इसकी संभावना भी कम ही है। इसलिए कि पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था में उभरी खामियों की वजह तकनीकी कमजोरियां नहीं हैं। इसकी कुछ वजहें नीतिगत हैं, जबकि ज्यादा दिक्कत सिस्टम में फैले कथित भ्रष्टाचार से उभरी है। यहां इसे अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि कितना भी दोषमुक्त डिजिटल सिस्टम कायम कर लिया जाए, वह संदिग्ध नियुक्तियों, संस्थाओं की कमजोरी, और शासन–तंत्र में नैतिकता के ह्रास से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की भरपाई नहीं कर सकता। ना ही उससे शिक्षा को मुनाफे के कारोबार में तब्दील करने वाली नीतियों से बनी स्थिति का समाधान ढूंढा जा सकता है। पेपर लीक के हालिया मामलों में अंदर तक पहुंच रखने वाले लोगों, कोचिंग संस्थानों, और लीक पेपर खरीदने को तैयार लोगों के बाजार की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। नीलेकणी समिति इसका क्या समाधान पेश करेगी? अतरू मामला व्यवस्थागत है, जिसका सीधा संबंध राजनीतिक इच्छाशक्ति से है। इस स्थिति को सरकार सचमुच बदलना चाहती है, इसके विश्वसनीय संकेत अभी नहीं मिले हैं।

मिलावटखोरों के खिलाफ भी करना पड़ेगा देशव्यापी आंदोलन

संतोष

संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है और वहीं देश के तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर भी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें भी लगातार निकल कर सामने आ रही है, जिसपर बड़े पैमाने पर चर्चा, वाद–संवाद और कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश के सभी लोगों के जीवन से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने का समय किसी के पास नहीं है। सत्ता में बैठने वाली किसी भी सरकार (चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो) के पास इसके समाधान का कोई स्थायी फॉर्मूला या विजन नहीं है, विपक्ष के पास भी इस पर बात करने की फुर्सत नहीं है और सरकारी अधिकारी अपने में ही मस्त है। मिलावटखोरी की समस्या अब हमारे देश की सबसे बड़ी भयावह समस्या बनती जा रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए अब बड़े स्तर पर कदम उठाए बिना कोई बात नहीं बनेगी। देश में कानून भी है, नियम भी है, निगरानी के लिए विभाग भी है और अधिकारी भी है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मिलावटखोरों को किसी भी बात का कोई डर ही नहीं है। इसे भी पढ़ेंरू उन्नत बचपन की पहली शर्त– स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भविष्य हाल ही में देश के एक बड़े अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जो दावा किया है, उसने सबकी नींदे उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की कई आटा मिलों में गेंहू के आटे में सफेद पत्थर का चूरा यानी स्टोन पाउडर मिलाया जा रहा है। मुनाफाखोरी के लालच में ये मिलावटखोर हमें पत्थर वाले आटे से बनी रोटी खाने को मजबूर कर रहे हैं। जबकि ये भी जानते हैं कि इस मिलावटी आटे से बनी रोटी को खाने से लोगों के शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। आजकल लोगों के घरों से लेकर, फास्ट फूड, शादी–ब्याह और पार्टियों तक में सबसे ज्यादा पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। कई एक्सपर्टध् जिम ट्रेनर तो बॉडी को मजबूत बनाने के लिए भी पनीर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन पनीर में मैदा या अरारोट मिलाना और स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं वनस्पति तेल का इस्तेमाल कर सिंथेटिक या नकली पनीर बनाना तो आम बात हो गई है। बल्कि ऐसे गंभीर मामले भी कई बार सामने आए हैं, कि डिटर्जेंट या यूरिया से बने दूध का भी इस्तेमाल कर पनीर बनाया और बेचा जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही, राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि असली पनीर बताकर इसे बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करना है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने आदेश में सख्त शब्दों में कहा कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर को लेकर ऐसा ही फैसला कर चुकी है। सबसे अधिक दुःखद और परेशानी में डालने वाला तथ्य तो यह है कि देश की नामी–गिरामी कंपनियां भी उपभोक्ताओं को धोखा देने का कोई मौका नहीं चूकती है। रोजमर्रा की जरूरत का कई सामान बेचने वाली एफएमसीजी कंपनी डाबर को लेकर भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर द्वारा किए जा रहे श 100: प्योरश, श100: ऑर्गेनिकश और श100: नेचुरलश जैसे दावों को भ्रामक बताते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। इन प्रोडक्ट्स में शहद, गाय का देसी घी, तिल का तेल और नारियल पानी जैसी कई चीजें शामिल हैं। डाबर को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है। इससे पहले भी कई नामी–गिरामी और बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यही कंपनियां जब विदेश खासकर अमेरिका या यूरोपीय देशों में कोई सामान बेचती है तो उसकी क्वालिटी का खास ध्यान रखती है लेकिन भारतीयों के लिए इनका एटीट्यूड शसब चलता है टाइपश ही होता है। लोग पैसे खर्च करने

को तैयार हैं ताकि उन्हें शुद्ध आटा, दाल, चावल, मसाले, चीनी, दूध, घी, खाद्य तेल, सब्जियां, पनीर, शहद, पानी और अन्य सामान मिल सके। लेकिन ज्यादा खर्च के बाद भी उनके साथ न केवल ठगी की जा रही है बल्कि लोग गंभीर बीमारियों के भी शिकार होकर मरते भी जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से इस भयावह समस्या का समाधान हो जाएगा, कतई नहीं। इसके लिए युद्धस्तर पर एक मिशन के तहत कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। नकली सामानों को बनने के स्तर पर ही रोकना होगा, इसके लिए उत्तरदायी विभाग में मैन पावर बढ़ाने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। इससे जुड़े विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हर महीने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी ऑनलाइन भरना चाहिए। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फैसले की समय सीमा भी तय करनी होगी। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कई अन्य कदम भी उठाने होंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमारी सरकार, अधिकारी, अदालत और नेता..ये सब इसके लिए तैयार हैं?

प्रश्नपत्र लीक विरोधी कानून पारित होने से भाजपा छात्रों का भरोसा जीत सकेगी

कल्याणी

एशियाई और प्रवासी श्जेनरेशन जेडश का भरोसा दोबारा जीतने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत होगी। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिसमें पार्टी खुद को एक ऐसी प्रगतिशील पार्टी के तौर पर पेश कर सके जो सभी वर्गों, जिसमें श्जेनरेशन

जेडश भी शामिल है, की आवाज को अहमियत देती हो। भारतीय राजनीति में श्जेनरेशन जेडश की अहम भूमिका है, इसलिए भाजपा को उनके बीच अपनी छवि बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। भारत में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने इतिहास के एक अहम मोड़ का सामना कर रही है। उसे यह सोचने की जरूरत है कि जेन जेड को कैसे जोड़ा जाए। मौजूदा मोदी सरकार को जेन जेड के साथ जूझना पड़ा, जिसने एक अचानक आंदोलन शुरू कर दिया जिससे सरकार हैरान रह गई। यह ग्रुप आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं की वजह से बदला है। नए प्रश्नपत्र लीक विरोधी कानून का मकसद परीक्षा सम्बंधी सरकारी कामों में पारदर्शिता को बेहतर बनाना है।जेनरेशन जेड को श्भुला दी गयी पीढ़ीश या बड़े बेबी बूमर और मिलेनियल ग्रुप के श्बीच का बच्चाश बताया गया है। इस पीढ़ी की खासियत आजादी, व्यावहारिक सोच और पहले से मौजूद संस्थाओं के प्रति शक की एक अलग भावना है। जेनरेशन जेड ने आर्थिक मंदी, इंटरनेट का आना और शरूरी राजनीतिक बदलावों सहित देश और दुनिया भर में कई अहम घटनाओं का अनुभव किया है। इस ग्रुप के कई लोगों को हाल के सालों में रोजगार बाजार में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वे उदारीकरण नीति के असर से प्रभावित हुए, जिससे मौके और अनिश्चितता दोनों मिले। यह पीढ़ी असलियत और व्यावहारिकता को महत्व देती है, और खोखले वादों के बजाय असली फायदों पर ध्यान देती है। जेनरेशन जेड के लिए, इसका मतलब है कि वे ध्यान से देखेंगे कि प्रश्नपत्र लीक विरोधी कानून असली जिंदगी पर कैसे असर डालता है। उनका समर्थन पाने के लिए, यह साफ तौर पर बताना जारूरी है कि कानून का मकसद क्या है और यह लोगों की सुरक्षा कैसे करता है। पिछले हफ्ध्ते, संसद ने राष्ट्रीय और जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकने वाली लीक को रोकने के लिए लीक विरोधी विधेयक पारित किया। इसकी मिली–जुली समीक्षा हुई। यह इस बारे में जरूरी सवाल उठाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। आलोचकों का मानना है कि संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा जारूरी है, लेकिन विधेयक का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उन्हें चिंता है कि यह बोलने की आजादी जैसी आजाादी को कमजोर कर सकता है और अलग–अलग नजरियों के लिए जगह कम कर सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्नपत्र लीक विरोधी विधेयक परीक्षाओं में जानकारी लीक होने से रोकने के लिए बनाया गया था।ये चिंताएं जेनरेशन जेड के लिए बहुत जरूरी हैं, जो सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को महत्व देते हैं। कई जेन जेड छात्र इस कानून को पिछली सरकारी कार्रवाइयों का दोहराना मात्र मानते हैं, जहां सुरक्षा के लिए बने कानूनों का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया गया था। वे जाहिर तौर पर सावधान और शक करने वाले हैं।जेन जेड को वापस जीतने के लिए भाजपा को एक साफ रणनीति की जरूरत है। ऐसी रणनीति में नीति को बढ़ावा देने या गारंटी वाले नतीजों को सामने लाने से कहीं ज़्यादा कुछ होना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने में कई और तरीके मदद कर सकते हैं।पहला, टाउन हॉल और सोशल मीडिया के जरिए जेनरेशन जेड के साथ असली जुड़ाव उन्हें सम्मान और फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल महसूस करा सकता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी के साथ उनका सम्पर्क मजबूत होता है। दूसरा, आमने–सामने का जुड़ाव मतदाताओं के लिए समुदाय और पुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं, खासकर जेन जेड में से ज़्यादा टेक–सैवी लोगों को अपील करते हुए।तीसरा, लीक विरोधी विधेयक के मकसद और सुरक्षात्मक उपायों को साफ तौर पर समझाकर पारदर्शिता को प्राथमिकता देने से जेनरेशन जेड को भरोसा महसूस हो सकता है और वे मोदी सरकार के उनके हितों के प्रति प्रतिबद्धता पर भरोसा कर सकते हैं। चौथा, इन्फोग्राफिक्स और पब्लिक बुलेटिन जैसे आसान फॉर्मेट में जानकारी शेयर करने से ऐसी पीढ़ी आकर्षित हो सकती है जो जल्दी और साफ जवाब चाहती है। इसके अलावा, चर्चा में विशेषज्ञों को शामिल करने से पार्टी की विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है और यह दिखा सकती है कि यह सबको साथ लेकर चलने वाली और सुनने वाली पार्टी है। पांचवीं बात, भाजपा को उन क्षेत्रों में अपनी सफलताओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना और प्रचारित करना चाहिए जो जेनरेशन जेड के मूल्यों से मेल खाते हैं। आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन, दक्षता विकास पहल, और डिजिटल प्रशासन में सफलता, ये सभी ऐसे विषय हैं जो इस ग्रुप पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। छठी बात, ऐसे काम के लिए विकास की परियोजनाओं और नीतियों पर जोर देना, जिनका सीधा असर जेन जेड समूह की जिंदगी पर पड़ा है, उनकी भलाई के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जेनरेशन जेड को व्यक्तिगत अधिकार की महत्ता के बारे में भरोसा दिलाना सबसे जरूरी है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि प्रश्नपत्र लीक विरोधी कानून लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बल प्रदान करता है। उन्हें मौजूद सुरक्षा उपाय दिखाने होंगे, यह बताना होगा कि स्वतंत्र निगरानी होगी, और यह प्रचार करना होगा कि लोगों के पास अपनी चिंताएं बताने के तरीके हैं। इससे इस शक करने वाले समूह के साथ भरोसे की कमी को कम करने में मदद मिल सकती है। सातवीं बात, नागरिक समाज को शामिल करके और शासन और नीति के बारे में चर्चा में अलग–अलग आवाजों को शामिल करके, भाजपा एक ऐसे लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में अपने निवेश को दिखा सकती है जो सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देता है। भाजपा सम्पर्क अभियान, नीति पर चर्चा और शैक्षणिक अभियान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है। आंकड़ों का विश्लेषण करके और सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करके, पार्टी अपने संदेश उन मुद्दों पर फोकस कर सकती है जो जेनरेशन जेड के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। यह तरीका यह पक्का करने में मदद करेगा कि संवाद उनसे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े। कानून बना परन्तु भाजपा के लिए पीढ़ीगत भरोसा फिर से हासिल करना एक चुनौती है। यह पार्टी के लिए अपने नजरिए को बदलने और जवाबदेही व पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का एक मौका भी है। श्जेनरेशन जेड्य का भरोसा दोबारा जीतने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत होगी। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिसमें पार्टी खुद को एक ऐसी प्रगतिशील पार्टी के तौर पर पेश कर सके जो सभी वर्गों, जिसमें श्जेनरेशन जेडश भी शामिल है, की आवाज को अहमियत देती हो। भारतीय राजनीति में श्जेनरेशन जेडश की अहम भूमिका है, इसलिए भाजपा को उनके बीच अपनी छवि बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। साफ रणनीतियों और सच्चे जुड़ाव के जरिए भाजपा श्जेनरेशन जेडश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकती है।

अंत में अब कॉकरोच का लेबल

हरिशंकर व्यास

सन् 2026 की 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच भारत में वह हुआ, जिसकी दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश ने कल्पना नहीं की। दुनिया के अखबारों, टीवी चौनलों और डिजिटल मंचों पर भारत बतौर श्कॉकरोचश्य की पहचान के साथ उभरा। कभी श्सांप–संपेरों के हिंदुस्तान्य की इमेज थी। पर 1947 में स्वतंत्रता के बाद के दशकों में लोकतंत्र, भारत–निर्माण, आईटी, उभरती आर्थिकी, परमाणु ताकत, आईआईटी–आईआईएम सहित शिक्षा की बेहतरी तथा विशाल जनसंख्या के बाजार के नाते भारत प्रतिष्ठित हुआ। वह सब अब हाशिए में है और अब भारत श्कॉकरोचश्य है। भारत में मनुष्य, नवजात पीढ़ी श्कॉकरोचश्य है, जिस पर लाठियां, पैलेट गन की गोलियां बरसी। यह वैश्विक अजूबा है और तभी दुनिया के हर कोने में अखबारों के पहले पेज पर, बैनर हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज की तरह छपा। सवाल है, कौन दोषी, किसने कॉकरोच भारत बनाया है? क्या संघ परिवार और उसके प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं? इसलिए श्कॉकरोचश्य फर्जी हिंदू राष्ट्र, फर्जी अमृतकाल का वह कलंक है, जिससे भले मोदी सरकार और भक्त हिंदू शर्मिंदा न हों, लेकिन विश्व मानव समाज अवश्य 145 करोड़ लोगों के भारत को जुगुप्सा, वितृष्णा से देख, समझ रहा है। सोचें, इक्कीसवीं सदी में दुनिया में आगे भारत अब क्या इमेज लिए है? एक ऐसा देश, जो स्वयं को श्विश्वगुरुश्य, श्लोकतंत्र की जननीश्य, श्विकसित भारतश्य और श्विश्वबंधुश्य बताता है, वहां श्कॉकरोचश्य है, श्कॉकरोच राजनीतिश्य है, श्कॉकरोच आर्थिकीश्य है, आदि–आदि। मोदी ने, अमित शाह ने पहले भारत के नागरिकों के आगे अनागरिक होने की तलवार लटकाई। पश्चिम बंगाल के लाखों दस्तावेजयुक्त वैध मतदाताओं को अनागरिक बनाकर उन्हें मताधिकार से बाहर किया। इसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने अपराध नहीं माना। फिर पूरे भारत के नागरिकों में ही मनुष्य को सर्वोच्च अदालत से श्कॉकरोचश्य परजीवी होने की तख्ती मिली! बावजूद इसके हिंदू राष्ट्र के भक्त हिंदुओं को शर्म नहीं आई, न ग्लानि हुई। इन हिंदुओं के हिंदू होने के डीएनए की सचमुच जांच होनी चाहिए। ये कौन से, क्या हिंदू हैं, इसका जवाब सनातन धर्म का शायद ही कोई ग्रंथ दे पाए। मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं और मुझे इतना सामान्य ज्ञान है कि सनातन धर्म में मानव जन्म को परम प्राप्ति कहा गया है। जन्म–जन्मांतर के विश्वासी हम सनातनियों का मूल सूत्र है कि मनुष्य, ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है। भगवान ने (श्रीमद्भागवत पुराण 11.9.29) अपनी मायाशक्ति से वृक्ष, सरीसृप (सांप आदि), पशु, पक्षी, मच्छर, मछलियां आदि अनेक योनियां बनाईं। परंतु उन्हें तब तक संतोष नहीं हुआ, जब तक उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना नहीं की। और ईश्वर स्वयं मनुष्य शरीर में ब्रह्म (ईश्वर) को जानने और देखने की बुद्धि देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा ही आदि शंकराचार्य का दिया सूत्र (विवेकचूड़ामणि, श्लोक 2) है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। मनुष्य होने के बाद पुरुषत्व, फिर वैदिक धर्म का मार्ग जानना, फिर विद्वान होना, और उसके बाद आत्मा–अनात्मा का विवेक प्राप्त करके ब्रह्म में स्थित होना, यह सब सौ करोड़ जन्मों के पुण्यों के बिना संभव नहीं है। तभी, जब मैंने चीफ जस्टिस का श्कॉकरोचश्य वाला वाक्य और बाद में उनकी सफाई सुनी, तो बतौर ब्राह्मण मुझे ग्लानि हुई कि हम आज के ब्राह्मण कैसे हैं! कितने अविवेकी, बुद्धिहीन हो गए हैं! देश की सर्वोच्च अदालत का चीफ जस्टिस मनुष्य पर श्कॉकरोचश्य का लेबल चस्पां कर रहा है! जाहिर है, चीफ जस्टिस का विवेक भी नरेंद्र मोदी नाम के कथित कल्कि अवतार के समय में ब्राह्मणों के विवेक, पुरुषत्व, ज्ञान और बुद्धि, सभी के पतन की बानगी है। सोचें, गंभीरता से सोचें कि चीफ जस्टिस के साथी जजों से लेकर सर्वज्ञ, अजैविक भगवान नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्रियों, संघ और हिंदू साधु–संतों में किसी के भीतर भी इस शब्द को बदलवाने, शब्द–वापसी, पछतावा, शर्म या खेद प्रकट कराने की बुद्धि या हिम्मत नहीं आई। जबकि आदि शंकराचार्य ने मनुष्य के पुरुषत्व (सत्यनिष्ठ निर्भयता), विद्वत्ता तथा आत्मा–अनात्मा के विवेक के माध्यम से ब्रह्म में स्थित होने तक की क्षमता में हर मनुष्य से मानवीय व्यवहार और संवेदना की अपेक्षा की है। जार्ज ऑरवेल का एक महान उपन्यास है, श्एनिमल फार्मश्य। इसमें मनुष्य की प्रवृत्तियों की वास्तविकताओं पर पशुओं के जंगल राज की कहानी है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे सुअर सत्ता हथिया लेते हैं और समानता के नाम पर नया अत्याचार खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऑरवेल भी यह नहीं सोच सकते थे कि किसी लोकतंत्र में, मानव समाज में मनुष्यों की तुलना कीड़े–मकोड़ों, कॉकरोचों से होगी और शासन फिर इन कॉकरोचों को आंसू गैस के गोलों से खत्म करने के आदेश देगा। इसलिए मसला गहरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक को (भले वह परजीवी हो) श्कॉकरोचश्य करार देना नए भारत के वर्तमान और भविष्य की दशा–दिशा है। पिछले बारह वर्षों से सरकार ने नौजवानों (बहुसंख्य आबादी को ही) अवसरों से वंचित किया है।

सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं

अजीत द्विवेदी

दुनिया के संभवतरू किसी दूसरे देश में नैतिकता की उतनी बात नहीं होती होंगी, जितनी भारत में होती हैं। भारत ने दया, करुणा, सत्य, प्रेम, भाईचारे आदि के जितने प्रतीक गढ़े हैं, दुनिया के किसी और देश में उतने नहीं होंगे। भारत में तो एक सतयुग ही था, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र थे। लेकिन यह भी सही है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे, करुणा, दया आदि से जितनी दूरी भारत में है उतनी शायद ही कहीं और होगी। इस पर लंबी बहस हो सकती है। इसलिए उसमें जाने की जरुरत नहीं है। लेकिन दुनिया के जिन देशों में सत्य और नैतिकता आदि का ढोल रोज नहीं बताया जाता है वहां लोग ज्यादा नैतिक होते हैं। वहां लोग नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अगर कोई अपराध किया है तो उसे भी स्वीकार करके सजा पाते हैं। भारत में कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता है और अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया व्यक्ति भी अदालत में खड़े होकर कहता है कि वह बेकसूर है और उसका पूरा परिवार और ज्यादातर मामलों में पूरी जाति उसके बचाव में खड़ी होती है। भारत की राजनीति में भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। नैतिक जिम्मेदारी लेकर कुछ मंत्रियों आदि ने जरूर इस्तीफे दिए, जिनकी आज तक चर्चा होती है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया या नीतीश कुमार का जिक्र किया जाता है। यह संयोग है कि इन तीनों के इस्तीफे ट्रेन दुर्घटना को लेकर हुए थे। इनके रेल मंत्री रहते ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। यह अलग बात है कि रेल मंत्रालय में विफल होने के बाद भी इन सभी लोगों को दूसरे मंत्रालयों में अहम जिम्मेदारी मिली। लाल बहादुर शास्त्री तो बाद में प्रधानमंत्री बने। बहरहाल, भारत में गंभीर से गंभीर विफलता या आर्थिक अपराध में शामिल होने के आरोपों के बाद भी इस्तीफा कराना बड़ा मुश्किल होता है। आर्थिक अपराध के मामलों में तो अब गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी नेता इस्तीफा नहीं देते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने कमाल की मिसाल बनाई। वे कई महीने जेल में रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने थोड़ी शर्म दिखाई और गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले इस्तीफा दे दिया। अगर गिरफ्तारी की बाध्यता नहीं होती तो वे भी इस्तीफा नहीं देते। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत में केंद्र या राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी विवाद में फंसने या अपनी कैसी भी विफलता के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं? इसे दो पहलुओं से देख सकते हैं। एक आपराधिक मामला और दूसरा विफलता व नैतिकता का मामला। जहां तक आपराधिक मामलों में फंसने पर इस्तीफे का सवाल है तो वह इसलिए आसानी से नहीं होता है क्योंकि भारत में पहले से जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं ऐसे, सैकड़ों लोग सांसद और विधायक चुने गए हैं। सवाल है जब गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने और उनकी जानकारी सार्वजनिक होने के बावजूद जनता उनको चुन देती है तो चुने जाने के बाद किए गए किसी अपराध के लिए वे क्यों इस्तीफा देंगे? जब जनता ने उनको सांसद चुन दिया है तो वे केंद्र में मंत्री बनने के योग्य हैं और जनता ने विधायक चुना है तो वे राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। ऐसे में उनके और जनता के बीच में नैतिकता की बात कहां से आ गई! उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जानने के बाद भी अगर जनता ने चुना है तो वे वैसे ही किसी अन्य अपराध के मामले में भी क्यों इस्तीफा देंगे? तभी भारत में ऐसे मामलों में भी जोर जबरदस्ती ही इस्तीफा होता है। गिरफ्तार होने या गिरफ्तारी की नौबत आने या पार्टी व सरकार के प्रमुख की ओर से राजनीतिक नुकसान की आशंका देख कर दबाव डालने के बाद ही इस्तीफा होता है।

अब रही जिम्मेदारी के निर्वहन में विफलता की बात तो उसमें भी आजादी के बाद से ही यह परंपरा चलती आ रही है कि इस्तीफा जोर जबरदस्ती ही होगा। ध्यान रहे भारत में पहला हाई प्रोफाइल इस्तीफा वीके कृष्ण मेनन का हुआ था। चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर दबाव था कि वे इस्तीफा दें। लेकिन वे इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। जब जन दबाव बहुत बढ़ा तो अंत में उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि जयराम रमेश ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है, श्अ चेकर्ड ब्रिलियंसरू द मेनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन्य, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कृष्ण मेनन तो बहुत पहले इस्तीफा देने को तैयार थे लेकिन उन्हें रोका गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मानते थे कि चीन के साथ युद्ध में पराजय का मेनन से कोई संबंध नहीं है। फिर वे क्यों इस्तीफा देंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही बातें सुन कर क्या कृष्ण मेनन के इस्तीफे की कहानी से समानता नहीं दिखती है? ध्यान रहे पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत पहले इस्तीफा देना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को लगता था कि पेपर लीक होने से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पेपर लीक होने के तुरंत बाद सक्रियता दिखाई। सारे आरोपी पकड़े गए और रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा करा ली गई ताकि छात्रों का एक साल बरबाद न हो। इसके बाद भी उनका इस्तीफा हुआ तो उसका कारण यही है कि जन दबाव बहुत बढ़ गया यानी जोर जबरदस्ती से ही उनका इस्तीफा हुआ।

सोचें, पेपर लीक कितनी बड़ी विफलता है! एक मंत्री के कार्यकाल में दो बार नीट यूजी जैसी विशाल अखिल भारतीय परीक्षा के पेपर लीक हो जाएं तो उससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? आश्चर्य यह है कि 2024 के शुरू में बजट सत्र में पेपर लीक का कठोर कानून बना था और मई में पेपर लीक हो गया, उसके बाद भी जून में जब नई सरकार बनी तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया! फिर 2026 के मई में नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया और धर्मेंद्र प्रधान कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे।

यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है। यह भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का मामला है, जहां हर व्यक्ति चाहता है कि जवाबदेही और नैतिकता का तकाजा दूसरे पर लागू हो। अपनी जवाबदेही और नैतिकता का ध्यान किसी को नहीं रहता है। जोर जबरदस्ती न हो तो न वीके कृष्ण मेनन का इस्तीफा होता और न धर्मेंद्र प्रधान का। याद करें कैसे कारगिल युद्ध के समय ताबूत घोटाला खुला था और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने कितनी मुश्किल से इस्तीफा दिया था। ऐसे ही दबाव नहीं होता और पार्टियों को चुनावी नुकसान का भय नहीं होता तो न ए राजा इस्तीफा देते और न अशोक चव्हाण की विदाई होती। महिलाओं का दबाव नहीं होता तो एमजे अकबर का भी इस्तीफा नहीं होता। सोचें, इंगलैंड में क्रिस्टीन किलर कांड में एक मंत्री लॉर्ड प्रोफ्यूमो का नाम आया था तो प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में मी टू के उतने बड़े मुद्दे में एमजे अकबर फंसे तो उनका भी इस्तीफा मुश्किल से हुआ और दुनिया के सबसे बड़े सेक्स अपराधी एपस्टीन के साथ संबंधों का खुलासा होने के बाद भी हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं हुआ।

गुलाबो किन्नर गिरफ्तार जानलेवा हमले और हिंसक झड़प मामले में पुलिस कार्रवाई

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। शाहगंज कोतवाली पुलिस ने बधाई लेने के क्षेत्राधिकार को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में एक किन्नर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शुक्रवार दोपहर 12 बजे की गई। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ था, जिससे इलाके में अफरा–तफरी मच गई थी। यह गिरफ्तारी 6 अगस्त को दर्ज हुए जानलेवा हमले के एक मामले से संबंधित है। डाली किन्नर ने इस संबंधा में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपनी गुरु शमा किन्नर, सीमा किन्नर और बिजली किन्नर सहित अन्य साथियों के साथ गुलाबो किन्नर के घर बातचीत करने गई थीं। डाली किन्नर के अनुसार, गुलाबो ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और छत पर चढ़कर गाली–गलौज की। आरोप है कि गुलाबो ने जानमाल की नियत से ईंटें फेंकीं। एक ईंट उनकी साथी सीला किन्नर के सिर में लगी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। घायल सीला किन्नर को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डाली किन्नर की लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धााराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी गुलाबो किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस गिरफ्तारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह और उपनिरीक्षक ओम प्रकाश पांडेय सहित थाना शाहगंज के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने बनाए नए कीर्तिमान, डेयरी कॉन्क्लेव में 17,994 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दुग्धशाला विकास विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जनपदीय स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव–2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. का संबोधन और विभागीय योजनाओं से संबंधित वीडियो वेब लिंक के माध्यम से प्रसारित किए गए।कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए दुग्ध आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2024–25 में लगभग 248 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 38.8 मिलियन मीट्रिक टन यानी करीब 16 प्रतिशत है, जिससे प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन तथा किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है।उन्होंने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से 17,994 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं 4,951 प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कॉन्क्लेव के दौरान पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ–संवर्धन योजना के 2,100 नवचयनित लाभार्थियों, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के 1,500 से अधिक तथा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के 450 से अधिक लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।दुग्ध आयुक्त ने बताया कि डेयरी क्षेत्र में 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक के 829 निवेश समझौते किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के तहत प्रदेश में 39 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण एवं शीतलीकरण क्षमता बढ़ी है, जिससे लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा निवेशकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 42 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है।कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। विभागीय विशेषज्ञों ने आधुनिक डेयरी तकनीक, वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, संतुलित पशु आहार तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।

विज्ञान संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत एवं मार्गदर्शन हेतु इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं मानव आनुवंशिकी विशेषज्ञ प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे रहे। प्रो. चौबे ने अपने प्रेरक व्याख्यान में भारत की जनसंख्या के इतिहास, मानव प्रवासन, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता तथा जीनोमिक्स के माध्यम से प्राचीन इतिहास को समझने की वैज्ञानिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को शोध, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. प्रदीप कुमार ने की। उन्होंने विज्ञान संकाय की शैक्षणिक उपलब्धियों, आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने छात्रवृत्तियों एवं छात्र सुविधाओं, जबकि मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रो. अविनाश डी. पाथर्डिकर ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं एवं अनुशासन संबंधी जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राधिका ने किया। इस अवसर पर प्रो. राम नारायण, डॉ. एस.पी. तिवारी, डॉ. विवेक पांडे, डॉ. संजीव कुमार मौर्य सहित विज्ञान संकाय के शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताते हुए इसे अपने विश्वविद्यालय जीवन की सफल शुरुआत के लिए उपयोगी बताया।

जिलाधिकारी ने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम सूचना संकलित बोर्ड लगाने के दिए निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में देर सायं कैम्प कार्यालय पर वी०बी०–जी० राम (जी०)– प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में सर्वप्रथम अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं के कार्य लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा प्रत्येक कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में एम०डी०एम शेडों, तालाबों एवं अमृत सरोवरों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि जनसामान्य को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने सक्रिय जॉब कार्ड धारकों के ई–केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र श्रमिकों का शत–प्रतिशत ई–केवाईसी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन मास्टर रोल जारी करने की स्थिति की समीक्षा की तथा कार्यों की आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से मास्टर रोल जारी करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को समय से मास्टर रोल जारी किए जाने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य में किसी प्रकार का विलंब न हो तथा आवश्यकतानुसार समय से मास्टर रोल जारी कर निर्माण कार्यों को गति प्रदान की जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने अमृत सरोवरों को मॉडल स्वरूप विकसित करने पर जोर देते हुए निर्देशित किया कि अमृत सरोवर पर ओपन जिम, ट्री गार्ड, वॉकिंग ट्रैक, समुचित प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग) सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे अमृत सरोवर आकर्षक होने के साथ–साथ स्थानीय नागरिकों के उपयोग एवं मनोरंजन का बेहतर केंद्र बन सके। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य प्रवेश द्वार पर ग्राम सूचना बोर्ड (टपससंहम प्दवितउंजपवद ठवंतक) स्थापित कराने के निर्देश दिए। इस बोर्ड पर गांव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कुल जनसंख्या, महिला एवं पुरुष जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, ग्राम प्रधान का नाम, भू–जल (ग्राउंड वाटर) की स्थिति, ग्राम की प्रमुख उपलब्धियां तथा विलेज सिटीजन चार्टर अंकित किया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं आगंतुकों को एक ही स्थान पर गांव की आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने उपायुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीसी–एनआरएलएम) को निर्देशित किया कि उक्त कार्यों का विस्तृत इस्टीमेट तैयार कराते हुए नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करें तथा सभी कार्यों को आगामी तीन माह के भीतर पूर्ण कराया जाए। बैठक में अन्नपूर्णा भवनों की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिया कि जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहां कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा सभी नवीन अन्नपूर्णा भवनों एवं अन्य नव–निर्मित सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु फ्लैग पोल की स्थापना अनिवार्य रूप से कराई जाए। जिलाधिकारी ने सभी विकास कार्यों के डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष बल देते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्य की डिजिटल डायरी तैयार की जाए, जिसमें कार्य प्रारंभ से पूर्ण होने तक की फोटो, प्रगति एवं अन्य आवश्यक विवरण सुरक्षित रखे जाएं। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा के अंतर्गत जारी मास्टर रोल की नियमित जांच करें, कार्यों का सतत फीडबैक प्राप्त करें तथा स्वयं फील्ड में जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें, जिससे कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त ग्राम पंचायतों में फॉगिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध रूप से फॉगिंग कर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, डी सी मनरेगा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

40 वर्षों की परंपरा के साथ निकली बोल बम काँवरिया संघ की भव्य शोभायात्रा, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालु

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर नगर की प्राचीनतम बोल बम काँवरिया संघ द्वारा शुक्रवार को भगवान शिव की भव्य कांवड़ शोभायात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। बीते 40 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत सैकड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। शोभायात्रा का शुभारंभ हनुमान घाट स्थित चौरा माता मंदिर में विधिवत पूजन–अर्चन के साथ हुआ। संघ के संरक्षक संतोष सेठ एवं महासचिव विमल सिंह ने नारियल फोड़कर यात्रा का शुभारंभ कराया, जबकि चेयरमैन प्रतिनिधि रामसूरत मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। हाथी, घोड़े, डीजे, भगवान शिव की आकर्षक झांकियों तथा द्वादश ज्योतिर्लिंग की मनमोहक प्रस्तुति ने शोभायात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान किया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से आई धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं और आमजन के आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभायात्रा सद्भावना पुल, कजगांव पड़ाव, ओलंदगंज, शाही पुल, चहारसू चौराहा, कोतवाली, सब्जी मंडी और सुतहट्टी बाजार होते हुए भंडारी रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से कांवरिये फरक्का एक्सप्रेस से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सुल्तानगंज पहुंचकर श्रद्धालु गंगाजल भरेंगे और वहां से पैदल यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। मार्ग में जगह–जगह महिलाओं ने श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। संघ के अध्यक्ष सुधीर साहू ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय है। भगवान शिव जनकल्याण के देवता हैं और उनके पूजन से समाज एवं राष्ट्र का कल्याण होता है। उन्होंने बताया कि संघ पिछले 40 वर्षों से लगातार बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर जलाभिषेक की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। महासचिव विमल सिंह ने सभी श्रद्धालुओं, समाजसेवी संस्थाओं, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। शोभायात्रा में संघ के संरक्षक अशोक सेठ, अजय साहू, गौतम सोनी, श्रवण कुमार चौरसिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शिवभक्त शामिल रहे।

संक्षिप्त खबरें

लोक एवं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण को मिलेगी नई गति, वार्षिक कार्ययोजना को सामान्य परिषद की मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक बुधवार को संस्कृति निदेशालय के सभागार में विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश की लोक एवं जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार–प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।बैठक में संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन, संसाधनों के बेहतर उपयोग, कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझावों पर चर्चा करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई।परिषद के सदस्यों ने प्रदेश की लोक एवं जनजातीय कला, लोक परंपराओं और लोक कलाकारों के संरक्षण तथा उनके प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से विचार–विमर्श किया। बैठक में संस्थान की आगामी सांस्कृतिक गतिविधियों, शोध एवं प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।अध्यक्ष दीपा रंजन ने संस्थान को प्रदेश की समृद्ध लोक एवं जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक सक्रिय, प्रभावी और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने, संस्थान की गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने तथा विलुप्तप्राय लोक धरोहरों, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजनों, लोक औषधीय ज्ञान और अन्य सांस्कृतिक परंपराओं का व्यवस्थित प्रलेखन, संरक्षण और संग्रहण करने पर बल दिया।

युवा पीढ़ी को विरासत से जोड़ने के लिए आयोजित हुआ शैक्षिक कार्यक्रम

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय संस्कृति और विरासत से युवा पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इतिहास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय के सहयोग से निदेशालय सभागार में रेजिडेंसी, छतर मंजिल और फरहत बख्श पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालक एवं बालिका विद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ तथा विद्याज्ञान स्कूल, सीतापुर के लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य पुरातत्व निदेशक रेनू द्विवेदी ने विद्यार्थियों से स्थानीय विरासत, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्मारकों को निकट से जानने तथा उनके संरक्षण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़कर ही नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बना सकती है।

5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं कराए गए पंचायत चुनाव

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराने की प्रक्रिया में हुई

देरी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगली बार पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो वर्ष पहले शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने पर ही संविधान के अनुच्छेद 243–ई में निर्धारित पांच वर्ष की अवधि के भीतर पंचायत चुनाव कराना संभव हो सकेगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया मई–2025 में शुरू की थी। इसके बावजूद अब तक पंचायत चुनाव नहीं हो सके हैं। पंचायतों का पांच वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। पीठ ने राज्य सरकार से रिकॉर्ड तलब किए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौजूदा पंचायत चुनाव पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं कराए जा सके। कोर्ट ने कहा कि वह यह भी देखना चाहता है कि चुनाव कराने में देरी के पीछे राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर सरकार ने समय पर चुनाव कराने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243–ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और इसके समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि इस संवैधानिक व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया पर्याप्त समय पहले शुरू करना जरूरी है।

विपक्ष ने तीन दिन तक सदन की कार्यवाही बाधित की, फिर भी सरकार ने सभी विधायी कार्य पूरे किए – ए.के. शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा और विधान परिषद के मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की विकासपरक नीतियों और ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नारेबाजी के बावजूद सरकार ने अपने सभी महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा किया और अनुपूरक बजट भी सफलतापूर्वक पारित कराया।सदन में अपने संबोधन के दौरान ए.के. शर्मा ने कहा कि आजादी के कई दशकों तक उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। लाखों घरों में बिजली नहीं थी और अनेक मजरों तक बिजली के खंभे और तार भी नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लगभग डेढ़ लाख मजरों तक बिजली पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक बिजली मांग की सफल आपूर्ति कर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इसे मजबूत ऊर्जा अवसंरचना, बेहतर प्रबंधन और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम बताया। उनके अनुसार नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि, वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में ए.के. शर्मा ने कहा कि विपक्ष की जनहित के मुद्दों के प्रति नकारात्मक सोच और सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने की प्रवृत्ति पूरे प्रदेश ने देखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण सदन के तीन दिन का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ।

किसानों और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सपा विधायकों का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समीप धरना देकर विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और राम धन की लूट जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं, खाद की किल्लत, ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा।विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी सपा विधायक लाल टोपी पहनकर पहुंचे और हाथों में विभिन्न मांगों एवं नारों वाली तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट का माहौल है तथा सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है।सपा विधायकों ने कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की कानून–व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की।विधानसभा परिसर में कुछ समय तक चले इस प्रदर्शन के बाद विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। विपक्ष ने संकेत दिए कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को वह सदन के भीतर भी प्रमुखता से उठाता रहेगा।

गले के कैंसर की पहचान के लिए बनाया अत्याधुनिक एआइ मॉडल

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रो. पुनीत मिश्रा के नेतृत्व में रिसर्च स्कालर मो. उस्मान, प्रज्ञनिक्स लैब्स के सिद्धार्थ चौरसिया और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की डॉ. गिनिका महाजन ने मिलकर गले के कैंसर की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक अत्याधुनिक एआइ मॉडल श्मेडिकल लार्ज कर्नल–स्माल कर्नल नेटश विकसित किया है। इसके तहत 1320 मरीजों की इमेज का अध्ययन किया गया। यह शोध पत्र नेचर पोर्टफोलियो के श्साइंटिफिक रिपोर्ट्सश में प्रकाशित हुआ है। प्रो. पुनीत मिश्रा बताते हैं कि लारेंजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फेफड़े के कैंसर के बाद सांस नली से जुड़ा दूसरा सबसे आम और जानलेवा कैंसर है।

तंबाकू, बीड़ी–सिगरेट और गुटखा के अत्यधिक सेवन के कारण उप्र सहित पूरे देश में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। शुरुआती अवस्था में कैंसर के सूक्ष्म लक्षणों को साधारण एंडोस्कोपी से पहचानना बेहद जटिल और समय लेने वाला होता है। समय पर सही पहचान न होने के कारण मरीजों का इलाज में देरी हो जाती है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है।

बीबीएयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के प्रबंध अध्ययन विभाग की ओर से बुधवार को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 रू विकसित भारत के लिए शिक्षा में परिवर्तन और उत्कृष्टता को बढ़ावा' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और विकसित भारत–2047 के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई।कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मुंबई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार लल्ला, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के संकायाध्यक्ष प्रो. अमित कुमार सिंह तथा कार्यक्रम समन्वयक प्रो. तरुणा भी मंचासीन रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विश्वविद्यालय कुलगीत के बाद अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. तरुणा ने संगोष्ठी की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी।अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आयुर्वेद के अनुसार माँ का दूध शिशु के लिए अमृत, सही स्तनपान तकनीक अपनाने का आह्वान

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा जनजागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष डॉ विजय जौहरी ने की। गोष्ठी का उद्देश्य भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का प्रचार–प्रसार, आयुर्वेदिक जीवनशैली के प्रति जनजागरण तथा सरकार की मंशानुरूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना था। मुख्य वक्ता डॉ सुमन अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद में माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान माना गया है। यह शिशु को संपूर्ण पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ओज, बल तथा स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बार शिशु को पहले एक ही स्तन से लगभग 15 से 20 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसे प्रारंभिक दूध के साथ–साथ अंत में आने वाला वसा एवं ऊर्जा से भरपूर दूध भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। डॉ सुमन अग्रवाल, डॉ रचना रस्तोगी, डॉ पल्लवी सक्सेना, डॉ आंचल गुप्ता एवं डॉ सुविया ने बताया कि सफल स्तनपान के लिए शिशु का स्तन से सही लगाव होना आवश्यक है। शिशु की ठोड़ी स्तन से सटी हो, उसका मुँह पर्याप्त खुला हो, निप्पल के नीचे का एरिओला कम तथा ऊपर का भाग अधिक दिखाई दे, और शिशु धीरे–धीरे गहरे घूंट लेकर दूध पीता दिखाई दे। यह संकेत है कि शिशु पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त कर रहा है और स्तनपान सही ढंग से हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध नवजात के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, इसलिए इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने सभी माताओं से छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा उसके बाद पूरक आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की अपील की। परिवार नियोजन के संदर्भ में चिकित्सकों ने बताया कि जन्म के बाद पहले छह माह तक यदि शिशु केवल माँ का दूध पी रहा हो और माँ का मासिक धर्म वापस न आया हो, तो स्तनपान गर्भधारण की संभावना को काफी कम कर सकता है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार परिवार नियोजन के अन्य सुरक्षित साधन भी अपनाने चाहिए।

अध्यक्षीय संबोधन में डॉ विजय जौहरी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भारत की गौरवशाली आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार–प्रसार, उसके वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन–जन तक पहुँचाने तथा समाज में आयुर्वेदिक आचार–विचार को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की मंशा के अनुरूप महासम्मेलन समय–समय पर जनहित में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अंत में सभी चिकित्सकों एवं उपस्थितजनों ने सफल स्तनपान को जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

सरकार मंशा को तार तार कर रहे विभागीय कर्मचारी

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। विकास की किरण गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार मंशा को विकास विभाग के लोग तार तार कर रहे हैं।सरकारी योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को गांवो में चौपालो का आयोजन कर रही है।परन्तु प्रचार प्रसार के अभाव में कुछ गिन चुने लोग ही पहुंच रहे हैं।वही पात्र लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पा रही है।कुल मिलाकर सरकार द्वारा चलाए जा रहा विकास जन चौपाल पूरी तरह फलाफ शो साबित हो रहा है।विकासखंड तारुन की ग्राम पंचायत सवरधीर में आयोजित चौपाल ग्राम प्रशासक की अनुपस्थिति में आयोजित हुआ।जिसमें ग्राम विकास अधिकारी रजनीश वर्मा ,नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति पर मौजूद रहे।उनके अलावा रोजगार सेवक बृजेश कुमार, पंचायत सहायक शोभा सिंह मौजूद रही कोई भी फरियादी जब अपनी समस्या लेकर 11:40 तक नहीं पहुंचा।इसी तरह ग्राम पंचायत बेला में प्रशासक दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल में ग्राम विकास अधिकारी संदीप कुमार ,नोडल अधिकारी के रूप में एडीओ एजी अजय कुमार सिंह मौजूद रहे।एकमात्र फरियादी आवास के लिए बिंदु ने अपनी समस्या 12:11 पर दर्ज कराई।प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था ग्राम विकास के तहत जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है।सिर्फ कर्मचारी अधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इतिश्री कर रहे हैं।

लापरवाही बरतने के आरोप मे एसएसपी ने किया सहादतगंज व फतेहगंज चौकी प्रभारी को निलंबित

अयोध्या। एसएससी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के चलते थाना कैंट क्षेत्र में तैनात प्रभारी चौकी सहादतगंज तथा कोतवाली नगर क्षेत्र में तैनात प्रभारी चौकी फतेहगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।माना जाए उन्होंने इन दोनों चौकी प्रभारियों को शिकायत कर्ताओं की शिकायत ना सुनने तथा अपने कार्यों के प्रति हीलाहवाली के चलते निलंबित किया है।सूत्रों के मुताबिक थाना कैंट क्षेत्र

मे चौकी प्रभारी सहादतगंज आशीष सिंह की शिकायत क्षेत्र के लोगों ने कई बार एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर से कर रहे थे। जिसके चलते एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वही कोतवाली नगर क्षेत्र में रहे फतेहगंज चौकी प्रभारी विकास गुप्ता की भी शिकायत भी सीधे एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर से हुई थी जिसे गंभीरता से लेते प्रभारी चौकी फतेहगंज को निलंबित कर दिया।एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर का मानना है कि अगर कोई भी पुलिस कर्मी कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए पाया गया तो उसका निलंबन होना तय है।

रोडवेज संयुक्त परिषद चुनाव मे अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष व अरविंद आचार्य मंत्री पद पर हुए निर्वाचित

अयोध्या। शुक्रवार को संयुक्त परिषद शाखा,अयोध्या रोडवेज का एक वर्षीय चुनाव रोडवेज परिसर मे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।चुनाव में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।जिसमे अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष,अरविंद आचार्या मंत्री, धर्मेंद्र सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष तथा डी.के. मिश्रा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए।वहीं महिला विंग में विनीता मिश्रा अध्यक्ष एवं नेहा तिवारी उपाध्यक्ष पद पर चुनी गईं। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री सहित अन्य पदाधिकारी को वहां पर उपस्थित कर्मियों ने फूल–मालाओं से स्वागत कर मिठाई खिलाई और उन्हें बधाई दी।नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह एवं मंत्री अरविंद आचार्य ने संयुक्त रूप से कहा कि संगठन की एकता, कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा।उन्होंने कहा कि संगठन में यदि कहीं कोई कमी होगी तो सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मिलकर उसे दूर करेंगे तथा संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

संक्षिप्त खबरें

गिराई में बैरिकेडिंग से भ्रमित हो रहे कांवड़िये

भदोही, (संवाददाता)। कांवड़ यात्रा को लेकर जिले में व्यवस्थाएं तो पुख्ता हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कमियों से कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति है। गोपीगंज के गिराई में फ्लाईओवर के पास बने कट के पास बैरिकेट लगाया है। इससे कांवड़िया भ्रमित होकर नगर में न आकर बाहर–बाहर निकल जा रहे हैं, जबकि नगर का उत्तरी लेन भी कांवड़ियों के लिए आरक्षित है। इसी तरह मिर्जापुर से जौनपुर के विभिन्न शिव मंदिरों में जाने वाले कांवड़ियों की लेन पर एक प्रदर्शनी के चलते सड़क पर ही बाइक खड़ी कर दी जा रही है। जिससे जाम की स्थिति बन रही है। सुरक्षित कावड़ यात्रा के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन नित नये प्रयोग कर रहा है। नगर में कांवड़ियों की भीड़ कम करने के लिए प्रयागराज–वाराणसी के बीच गिराई के पास गोपीगंज नगर के लिए खोले गए प्रवेश मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा कर हाईवे पर कावड़िया मार्ग का बोर्ड लगा दिया गया है। जिससे भ्रमित होकर कांवड़िया सीधे हाइवे होते हुए आगे निकल जा रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि कांवड़ियां नगर से होकर गुजरते थे तो नगर से ही खाने पीने का सामान लेते थे। साथ ही नगर के शिवालयों में दर्शन पूजन और विश्राम करते थे। इसी तरह औराई–मिर्जापुर रोड के किनारे इन दिनों हस्तशिल्प प्रदर्शनी का मेला लगा है, जहां दोपहर से लेकर आधी रात तक कांवड़ियां पर बाइक और चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं, जो कांवरियों के साथ ही जाम की भी स्थिति उत्पन्न कर रही है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिर्जापुर से जौनपुर जाने वाले पश्चिमी लेन पर कांवड़ियों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यातायात प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है। अगर ऐसा है तो खड़े वाहनों का चालान होगा।

एसएमएस सेवा नहीं देने वाली कंपनी पर 1.10 लाख रुपये लगाया जुर्माना

भदोही, (संवाददाता)। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को बैंगलुरु की एक एसएमएस जनरेट करने वाली कंपनी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं कंपनी को 64 हजार 900 रुपये भी वापस करने के निर्देश दिया। औराई स्थित सूर्या ट्रामा सेंटर ने कंपनी के खिलाफ पैसा लेने के बाद भी सुविधा उपलब्ध न कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिससे उससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी थी। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्रत रावत ने बताया कि सूर्या ट्रामा सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉ. रमन सिंह ने बैंगलुरु की एक एसएमएस जनरेट करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत की। बताया कि अस्पताल की ओर से मरीजों को चिकित्सक सुविधाओं और चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसएमएस सेवा की कंपनी से संपर्क किया। अस्पताल प्रबंधन ने 18 मार्च, 2025 को कंपनी को एसएमएस सेवा प्रदान करने के लिए 64900 रुपये भुगतान कर दिए। इसके बाद भी कंपनी की ओर से सेवा प्रदान नहीं की गई। अस्पताल प्रबंधन ने 22 फरवरी 2026 को कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर एसएमएस सेवा देने वाली कंपनी पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया।

आईआईटी छात्रा से दुष्कर्म मामले में सुनवाई

वाराणसी, (संवाददाता)। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से वर्ष 2023 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने वाले सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की। अदालत ने अगली सुनवाई 6 अगस्त तय करते हुए भारती एयरटेल के नोडल अधिकारी कौशलेन्द्र त्रिपाठी को गवाही के लिए तलब किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की अंतिम गवाही का दौर चल रहा है। आरोपी कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े वर्ष 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण संबंधी पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों ने अपने–अपने पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे। प्रकरण के अनुसार, वर्ष 1991 में पंडित स्वर्गीय सोमनाथ व्यास, पंडित स्वर्गीय रामरंग शर्मा और पंडित स्वर्गीय हरिहर पांडेय ने ज्ञानवापी मामले में मूल वाद दायर किया था, जो वर्तमान में अवर न्यायालय में लंबित है। वाद में पक्षकार अनुष्का तिवारी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की है कि वर्ष 1991 के इस मूल वाद को ज्ञानवापी से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ समेकित करते हुए इसे मुख्य वाद घोषित किया जाए। इस संबंध में पूर्व में दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका था,।

काशी नरेश विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश की मेरिट सूची जारी

भदोही, (संवाददाता)। काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी की है। बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र बृहस्पतिवार से छह अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। स्व–वित्तपोषित योजना के तहत संचालित अन्य विषयों के लिए भी यही तिथि लागू होगी। विश्वविद्यालय ने बीएससी (बायो), बीएससी (एग्रीकल्चर) और बीसीए पाठ्यक्रमों के लिए वरीयता सूची जारी की है। इन पाठ्यक्रमों के चयनित छात्रों को भी 14 अगस्त 2026 तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने वाले छात्रों के आवेदन पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा।

डॉ. वीके सारस्वत का युवाओं को संदेश – विकसित भारत के आर्किटेक्ट हैं युवा

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पद्मभूषण डॉ. विजय कुमार सारस्वत ने

विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत का निर्माण युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि आज के छात्र–छात्राएं विकसित भारत के आर्किटेक्ट हैं। इसलिए केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि यह सोचें कि अपने क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकते हैं और समाज को क्या नया दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि समृद्ध और मानवीय मूल्यों से युक्त समाज का निर्माण भी है। आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मशीनें इंसानों से अधिक तेज काम कर सकती हैं, लेकिन उनमें मानवीय संवेदनाएं और मूल्य नहीं होते। यही मानव की सबसे बड़ी ताकत है। डॉ. सारस्वत ने कहा कि नवाचार के लिए नेतृत्व क्षमता आवश्यक है। युवाओं को अनुसंधान और इनोवेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन चुनौतियों से दूसरे लोग पीछे हटते हैं, उन्हें स्वीकार कर समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रयोग करने का साहस रखने की अपील करते हुए कहा कि असफलता के डर से कभी पीछे न हटें। केवल सिमुलेशन या कल्पना से बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं होतीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में उतरकर काम करने से सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखें, अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। तभी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा।

राज्यमंत्री रजनी त्रिपाठी का युवाओं को संदेश - नौकरी मांगने नहीं, देने वाले बनें

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी त्रिपाठी ने कहा कि जीवन में चुनौतियां हर कदम पर आती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच सफलता का रास्ता भी निकलता है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसे बनें जो दूसरों को रोजगार देने की क्षमता विकसित करें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। आज प्रदेश एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है और औद्योगिक विकास, निवेश तथा रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे परिवेश में युवाओं के लिए संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राज्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा और संस्कार उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

छात्रवृत्ति योजनाओं के सफल संचालन को लेकर कार्यशाला का आयोजन

गोरखपुर, (संवाददाता)। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाने और आवेदन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से बुधवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में डीएम की अध्यक्षता में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों की बैठक व कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनपद के लगभग 700 शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, नोडल अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा जन सेवा केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए हजिला समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति योजना में इस वर्ष किए गए नए बदलावों की जानकारी दी और सभी शिक्षण संस्थानों से समयबद्ध तरीके से आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान की प्रोफाइल समय से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों के आवेदन में किसी प्रकार की समस्या न आए। कार्यशाला में छात्रवृत्ति की समय–सारणी, आवेदन प्रक्रिया और नई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित प्रधानाचार्यों, नोडल अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

निजी आईटीआई पर फर्जी नामांकन का आरोप, छात्रों ने थाने में दी तहरीर

गोरखपुर, (संवाददाता)। थाना क्षेत्र के भीटीरावत स्थित एक निजी आईटीआई के कई छात्रों ने प्रबंधन पर फर्जी नामांकन और पंजीकरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। आरोप है कि प्रवेश व पंजीकरण के नाम पर उनसे पूरी फीस ली गई लेकिन वैध पंजीकरण नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, फर्जी रोल नंबर के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा भी करा दी गई। शिकायतकर्ताओं में दीपक, विशाल कुमार, राहुल कुमार, अमरनाथ मौर्य, विकास और राकेश समेत कई छात्र शामिल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रवेश लिया था। निर्धारित शुल्क की रसीदें भी उनके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद अब तक उनका विधिवत पंजीकरण नहीं किया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन शिकायत करने पर डरा–धमका रहा है। छात्रों के अनुसार, बुधवार को जब वे अपनी शिकायत लेकर एसडीएम सहजनवा से मिलने पहुंचे तब संस्थान के कर्मचारियों ने उन्हें धमकाया और उनकी गाड़ियों के साथ–साथ उनका वीडियो व फोटो भी बनाया। पीड़ित छात्रों ने पुलिस को दी तहरीर में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संस्कृत विवि ने भी प्रो. ओझा को किया प्रतिबंधित, नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख लेने का आरोप

वाराणसी, (संवाददाता)। बीएचयू के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मानद प्रबंधक पद से हटाए जाने के बाद प्रो. ब्रज भूषण ओझा पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी प्रशासनिक कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें अपने सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक निकायों से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचनाओं और सामने आए आरोपों के संज्ञान में लेने के बाद किया गया है। बुधवार को विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग के प्रो. ब्रज भूषण ओझा को अब विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन बोर्ड, विशेषज्ञ पैनल, चयन समिति, परीक्षा, मूल्यांकन कार्य अथवा अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक निकायों में सदस्य या विशेषज्ञ के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार, यदि वह पहले से किसी समिति या दायित्व से जुड़े हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उससे मुक्त माना जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संस्थान की साख, निष्पक्षता और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से यह एहतियाती और प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

बीएसपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का किया स्वागत

गोरखपुर, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर का जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर सबसे वह अंबेडकर चौक पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। माल्यार्पण के पश्चात नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बीएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और मायावती के संदेश को जन–जन तक पहुंचाना है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।